नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 115
दि. 28.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आज से बजट सत्र का आगाज, सर्वदलीय बैठक में 35 से अधिक दलों की भागीदारी, सरकार ने VB-G RAM-G कानून पर चर्चा से किया इनकार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित कर राजनीतिक दलों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 35 से अधिक राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य आगामी बजट सत्र को सुचारू, सकारात्मक और व्यवस्थित तरीके से संचालित करना बताया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह संसद के कामकाज को बिना बाधा आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष ने भी अपने-अपने मुद्दे और चिंताएं बैठक के दौरान सामने रखीं।

बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो इस बार रविवार के दिन होगा। सरकार का कहना है कि यह सत्र आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां वैश्विक चुनौतियों, महंगाई, रोजगार और विकास की रफ्तार जैसे मुद्दे संसद के केंद्र में रहने वाले हैं।

सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह कह रहा है कि सरकार अपना विधायी एजेंडा साझा नहीं कर रही, जबकि परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति

के अभिभाषण के बाद ही सरकार संसद के सामने अपना विस्तृत विधायी एजेंडा रखती है। रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन सुनना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार चर्चा से भाग नहीं रही, बल्कि संसदीय परंपराओं के अनुसार आगे बढ़ रही है। हालांकि बैठक के दौरान एक अहम मुद्दा VB-G RAM-G कानून को लेकर सामने आया। विपक्षी दलों ने इस कानून पर संसद में चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार इस कानून को लेकर अभी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इस रुख को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई और इसे लोकतांत्रिक संवाद के खिलाफ बताया।

बैठक के बाद विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रियाओं से यह साफ हो गया कि बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अपने-अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे रखे। उन्होंने बताया कि प्रदूषण, SIR, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और आम जनता से जुड़े कई सवाल उठाए गए। सावंत के अनुसार विपक्ष चाहता है कि संसद में इन मुद्दों पर गंभीर और सार्थक चर्चा हो, ताकि आम लोगों की समस्याओं का समाधान निकल सके।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव ने सरकार के बजट को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम आदमी को कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उनके अनुसार यह बजट उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनके पास पहले से संपत्ति और संसाधन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान कम दिखाई देता है, जबकि यही मुद्दे आज देश की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बैठक के बाद सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल रही है। चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों का मामला हो या अमेरिका द्वारा बार-बार प्रधानमंत्री का अपमान किए जाने का मुद्दा, सरकार इन सब पर चुप्पी साधे हुए है। संजय सिंह के मुताबिक इस तरह की चुप्पी देश में चिंता और असंतोष पैदा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर संसद में खुलकर जवाब देना चाहिए।

संजय सिंह ने प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े कथित अपमान के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि यह केवल धार्मिक मामला नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और परंपराओं से जुड़ा विषय है। इसके अलावा उन्होंने SIR का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि SIR के नाम पर बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनके अनुसार इस मुद्दे पर संसद में पारदर्शी चर्चा जरूरी है।

सर्वदलीय बैठक में शामिल कई अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। कुछ सांसदों ने महंगाई, किसानों की आय, न्यूनतम समर्थन मूल्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कुछ दलों ने संघीय ढांचे, राज्यों के अधिकारों और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। विपक्ष का कहना है कि बजट सत्र केवल औपचारिकता न बनकर रह जाए, बल्कि इसमें देश के ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर बहस होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर फिर न्यायिक संग्राम सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

(जीएनएस)। नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिए जाने वाले आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के सामने आ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस जनहित याचिका पर दिया गया है, जिसमें वर्ष 2022 में गठित न्यायमूर्ति बंथिया आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर लिए गए सभी फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत के इस कदम से न केवल राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है, बल्कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की दिशा और दशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई। याचिका 'यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन' नामक संगठन की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि न्यायमूर्ति बंथिया आयोग ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी, वह संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुरूप नहीं है। संगठन का कहना है कि आयोग ने स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय के 'राजनीतिक पिछड़ेपन' का आकलन करने में न तो पर्याप्त वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और न ही ठोस व प्रामाणिक आंकड़ों का सहारा लिया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण तभी दिया जा सकता है, जब तीन शर्तें पूरी हों—एक समर्पित आयोग द्वारा राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन, उस अध्ययन के आधार पर ठोस डेटा प्रस्तुत किया जाना और कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न होना। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बंथिया आयोग इन शर्तों को पूरा करने में विफल रहा और उसने जल्दबाजी में रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। 'यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन' ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि केवल बंथिया आयोग की रिपोर्ट को रद्द करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार को एक नया और स्वतंत्र आयोग गठित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिका के अनुसार यह नया आयोग सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और पंचायतों में ओबीसी समुदाय की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का गहन अध्ययन करे। संगठन का कहना है कि जब तक प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर पर अलग-अलग आंकड़ों के आधार पर पिछड़ेपन का आकलन नहीं किया जाता, तब तक आरक्षण देना संविधान की भावना के खिलाफ होगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी दलील दी कि न्यायमूर्ति बंथिया आयोग को आरक्षण की सिफारिश करने का अधिकार ही नहीं था। उनका कहना था कि आयोग का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था, वह सीमित था, लेकिन उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे निष्कर्ष निकाले, जिनका सीधा असर चुनावी प्रक्रिया और आरक्षण नीति पर पड़ा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आयोग ने राज्य सरकार के दबाव में काम किया और निष्पक्षता के मानकों का पालन नहीं किया।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा यह मुद्दा पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है और अब इस नई याचिका को भी उन मामलों के साथ टैग किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनकर इस जटिल मसले पर कोई व्यापक और अंतिम निर्णय लेगी। नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का सवाल पिछले कई वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ है। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि बिना ठोस डेटा के आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बंथिया आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था।

हालांकि आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही उसके निष्कर्षों पर सवाल उठते रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों का कहना रहा है कि रिपोर्ट में पूरे राज्य के लिए एक समान निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय की राजनीतिक स्थिति भिन्न हो सकती है। इसी असंतोष का परिणाम अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस नई याचिका के रूप में सामने आया है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ओबीसी समुदाय महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है और स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण का सीधा असर सत्ता संतुलन पर पड़ता है। यदि सुप्रीम कोर्ट बंथिया आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाता है या उसे रद्द करता है, तो इससे न केवल चुनावों में देरी हो सकती है, बल्कि राज्य सरकार की रणनीति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संकेत देता है कि अदालत इस मामले में बेहद सतर्कता बरत रही है। कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आरक्षण जैसी संवेदनशील नीति केवल संवैधानिक दायरे में रहकर और ठोस तथ्यों के आधार पर ही लागू हो। वहीं, राज्य सरकार के सामने अब यह चुनौती है कि वह अदालत को यह भरोसा दिलाए कि बंथिया आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह वैध और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

भारत-ईयू ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता: 18 साल बाद 'मदर ऑफ ऑल डील्स', सस्ती होंगी लग्जरी कारें-शराब, खुलेगा दो अरब लोगों का बाजार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दुनिया की बदलती आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और यूरोपीय संघ ने इतिहास रचते हुए उस मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे बीते 18 वर्षों से अधूरा माना जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की मौजूदगी में भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनना सिर्फ एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति संतुलन को नया रूप देने वाला कदम माना जा रहा है। इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक ट्रेड एग्रीमेंट है, जो सीधे तौर पर करीब दो अरब लोगों के बाजार को जोड़ता है।

इस समझौते का सबसे प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। अब तक इम्पोर्टेड लग्जरी कारों पर 100 से 110 प्रतिशत तक लगने वाला भारी-भरकम टैरिफ घटकर करीब 10 प्रतिशत रह जाएगा। इसी तरह प्रीमियम यूरोपीय शराब, वाइन और स्पिरिट्स पर 150 प्रतिशत तक लगने वाला आयात शुल्क घटकर लगभग 20 प्रतिशत होने की राह साफ हो गई है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी कारें और फ्रांस-इटली की मशहूर वाइन भारतीय बाजार में कहीं अधिक सुलभ और किफायती होंगी। हालांकि सरकार का जोर इस बात पर है कि यह छूट चरणबद्ध

तरीके से लागू होगी, ताकि घरेलू उद्योगों को झटका न लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को साझा समृद्धि का नया खाका बताते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ का यह सहयोग न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि जब दुनिया में उथल-पुथल का माहौल है, तब भारत-ईयू साझेदारी विश्व व्यवस्था को संतुलन और भरोसे का संदेश देती है। पीएम मोदी के अनुसार यह समझौता समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने में भी सहयोग बढ़ाएगा, जिससे दोनों पक्ष भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी इसे दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश बताया कि भारत और यूरोपीय संघ विश्वसनीय साझेदार के रूप में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं। उनके मुताबिक यह करार दो अरब लोगों के बाजार के लिए अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता है, जो वैश्विक व्यापार की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। यूरोपीय नेतृत्व का मानना है कि एशिया में भारत जैसा मजबूत और लोकतांत्रिक साझेदार यूरोप के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है।

आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार पहले से ही मजबूत स्थिति में है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 136.53 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर रहा। इस समझौते के साथ ही यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार बन गया है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा ईयू बाजार में जाता है, जबकि यूरोप के कुल विदेशी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 9 प्रतिशत है। अब जब टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम होंगी, तो इन आंकड़ों में तेज उछाल की उम्मीद जताई जा रही है।

इस डील को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके तहत भारत के 9,000 से अधिक उत्पादों पर यूरोपीय संघ में आयात शुल्क कम या पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स-ज्वेलरी, लेदर, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा परिधान आयातक है और वित्त वर्ष 2024-25 में उसका कुल परिधान आयात 202.8 अरब डॉलर का रहा। ऐसे में भारतीय परिधान उद्योग के लिए यह समझौता सुनहरे अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते का असर केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि MSME सेक्टर को इससे नई जान मिलेगी। छोटे और मझोले उद्यमों को यूरोप जैसे बड़े और स्थिर बाजार में सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा, जिससे नए ऑर्डर, उत्पादन विस्तार और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही किसानों और मछुआरों को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि कृषि और समुद्री उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार में बेहतर दाम और स्थिर मांग उपलब्ध होगी।

सेवा क्षेत्र के लिए भी यह डील किसी गेम-चेंजर से कम नहीं मानी जा रही है। आईटी, फिनटेक, हेल्थ, एजुकेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज समेत करीब 144 सब-सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार में आसान एंट्री मिलेगी।

गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की पहल तेज, केंद्रीय मंत्रियों से मिले एन के पुरोहित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में गौ माता के विशेष स्थान को रेखांकित करते हुए गौधाम पथमेड़ा के आयोजन मंत्री एन के पुरोहित ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल तथा केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की।

इस मुलाकात के दौरान उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा और इसे केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक, नैतिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया। एन के पुरोहित ने कहा कि गौ माता भारतीय जीवन पद्धति की आधारशिला रही हैं और सदियों से कृषि, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण संतुलन तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूती देती आई हैं। उनका संरक्षण और सम्मान राष्ट्र के मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुलाकात के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस विषय पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा कार्यकाल में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि इस विषय से जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और सभी संबंधित पक्षों से संवाद किया जाएगा। वहीं, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि गौ माता का सम्मान भारतीय सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है और इसे राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने के प्रयासों में वे पूरा सहयोग देंगे।

एन के पुरोहित ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यदि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है तो यह देशभर में करोड़ों गौ भक्तों, किसानों और सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान होगा। उन्होंने इसे गौ रक्षा और गौ संवर्धन के लिए चल रहे आंदोलनों के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस मुलाकात को गौ संरक्षण से जुड़े प्रयासों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

चतरगला की बर्फीली चुनौती पर जीत, पांच–छह फीट बर्फ में फंसे 40 जवानों समेत 60 लोग सुरक्षित निकाले गए

(जीएनएस)। जम्मू। जम्मू-कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक बार फिर सीमा सड़क संगठन ने अपने साहस, कौशल और प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए बड़ा राहत अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। डोडा जिले के चतरगला दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण पांच से छह फीट मोटी बर्फ में फंसे राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 40 जवानों सहित कुल 60 लोगों को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत की बात यह रही कि इस कठिन और जोखिम भरे अभियान के दौरान किसी के भी घायल होने या जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि यह पूरा अभियान बीआरओ के 'प्रोजेक्ट संपर्क' के तहत चलाया गया। चतरगला दर्रा करीब 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लगातार करीब 40 घंटे तक हुई भारी बर्फबारी के कारण यह इलाका पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। सड़क पर हर जगह पांच से छह फीट तक बर्फ जम गई थी, जिससे न केवल सैन्य आवाजाही, बल्कि आम नागरिकों का निकलना भी असंभव हो गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ की 35 सीमा सड़क कार्य बल (बीआरटीएफ) की 118 सड़क निर्माण कंपनी (आरसीसी) को तत्काल अलर्ट किया गया। टीम ने 24 जनवरी को, भारी बर्फबारी थमने के ठीक एक दिन बाद, अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बचाव और सड़क बहाली अभियान शुरू किया। आधुनिक मशीनों, स्नो कटर और भारी उपकरणों के साथ जवानों ने दिन-रात काम करते हुए लगभग 38 किलोमीटर लंबी सड़क को बर्फ से साफ किया। ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और लगातार फिसलन भरे हालात के बावजूद बीआरओ कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और अभियान को निरंतर आगे बढ़ाया। लगातार प्रयासों के बाद 25 जनवरी की शाम तक चतरगला दर्रे का मार्ग खोल दिया गया। इसके साथ ही वहां फंसे 20 नागरिकों और '4 राष्ट्रीय राइफल्स' के 40 जवानों को उनके हथियारों और आवश्यक सामान के साथ सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और किसी भी तरह की जनहानि न होने से राहत अभियान पूरी तरह सफल माना गया। इस अभियान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सीमा सड़क संगठन केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा और संकट के समय जीवन रक्षक भूमिका निभाने में भी अग्रणी है। दुर्गम इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों के लिए बीआरओ की मौजूदगी भरोसे की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। चतरगला जैसे कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय साहस और समर्पण से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है।

संपादकीय

जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान

जब देश 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गर्व के साथ मना रहा है, तब यह अवसर केवल परेड, झांकियों और औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह समय आत्ममंथन का भी है—सत्ता में बैठे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के लिए, जो इस लोकतंत्र का हिस्सा है। गणतंत्र का अर्थ केवल अधिकारों की प्राप्ति नहीं, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन से भी जुड़ा है। लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है, जब सत्ता और समाज दोनों अपनी-अपनी जवाबदेही को गंभीरता से समझें और निभाएं।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान उसकी संवैधानिक संस्थाओं से होती है। संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया जैसी संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ हैं। इनकी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनपक्षधरता से ही लोकतंत्र की साख बनी रहती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि तंत्र जनतंत्र पर हावी हो जाए, यदि नियम-कानून आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसे हतोत्साहित करने लगें, तो लोकतांत्रिक भावना कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए जरूरी है कि शासन व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों का जीवन आसान बनाना हो और सत्ता व प्रशासन तक उनकी पहुंच सरल, सम्मानजनक और समयबद्ध हो। लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकारों के अच्छे कामकाज से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसके लिए जागरूक नागरिकों की सक्रिय भूमिका भी आवश्यक है। एक जिम्मेदार नागरिक केवल सुविधाओं और लाभों की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि व्यवस्था की कमियों पर सवाल भी उठाता है। संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पर नजर रखना, नीतियों को समझना और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखना नागरिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संदर्भ में स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया यदि जनहित को प्राथमिकता दे और सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखे, तो वह लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी बन सकता है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में समाज की सामूहिक शक्ति की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना या नीति को बदलाव के आंदोलन में बदलने की क्षमता समाज के सक्रिय सहयोग से ही आती है। डिजिटल भुगतान का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि आज दुनिया के लगभग आधे डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। यह उपलब्धि केवल तकनीकी विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि नागरिकों के विश्वास, सहभागिता और स्वीकार्यता का भी प्रमाण है। जब समाज किसी पहल को अपनाता है, तो वही पहल देश की पहचान बन जाती है। यही जनभागीदारी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। देश ने हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका कितनी निर्णायक होती है। मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। एक जागरूक मतदाता न केवल अपना वोट डालता है, बल्कि यह भी सोचता है कि वह किसे और क्यों चुन रहा है। भारतीय राजनीति में लंबे समय से धनबल, बाहुबल और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का प्रभाव चिंता का विषय रहा है। लेकिन इस स्थिति को बदलने की कुंजी भी मतदाताओं के हाथ में ही है। यदि नागरिक विवेकपूर्ण मतदान करें और ईमानदार, संवेदनशील तथा समाज से जुड़े उम्मीदवारों को चुनें, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का चरित्र स्वतः बदल सकता है। लोकतंत्र की यात्रा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक और आशाजनक संकेत है। बीते कुछ वर्षों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और कई राज्यों में सरकार गठन में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का भी परिचायक है। खेत-खलिहानों में काम करने वाली महिलाओं से लेकर अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिकों तक, सेना में सेवा देने से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश का नाम रोशन करने तक—भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। अब जरूरत है कि इस सहभागिता को और अधिक सशक्त बनाया जाए। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकारों की योजनाएं तभी सार्थक होंगी, जब वे महिलाओं के जीवन में वास्तविक और स्थायी बदलाव ला सकें। जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, आवास योजनाओं में संपत्ति पर अधिकार और स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी से करोड़ों महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। इन प्रयासों से न केवल उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि सामाजिक निर्णयों में उनकी आवाज भी मजबूत हुई है। हालांकि, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं।

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत के पास सबसे अधिक युवा हैं, जो ऊर्जा, नवाचार और परिवर्तन की अपार क्षमता रखते हैं। लेकिन यह जनसांख्यिकीय लाभ तभी वरदान बनेगा, जब युवाओं को पर्याप्त और समय पर रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असंतोष, निराशा और अस्थिरता को भी जन्म देती है।

क्रिकेट को रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने दें

> “ आज भारत और बांग्लादेश का युवा कहीं अधिक आकांक्षी और महत्वाकांक्षी हैं। इसीलिए क्रिकेट नई शुरुआत करने का एक माध्यम बन सकता है। दोनों पक्षों के बीच तनाव को खत्म कर सकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों के मौजूदा संकट में रोचक पहलू यह कि समाधान हेतु उपयुक्त तमाम घटक उसमें ही मौजूद हैं। भारत के लिए अवसर है कि नकारात्मक सोच वाले उन सभी विरोधियों की बाजी पलट दें जो 1971 के बाद से दो मुल्कों के बीच बेहद खास रिश्तों का पराभव चाहते हैं।

समाधान हेतु मुद्दों की सूची में शीर्ष पर क्रिकेट संकट है, जो एक पखवाड़े पहले हिंदू संगठनों द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के खेलने पर रोक लगाने की मांग से पैदा हुई। बीसीसीआई इस मांग पर झुक गई और युवा मुस्तफिजुर को हटाया गया। इससे क्रोधित हुए बांग्लादेशियों का गुस्सा थम नहीं रहा है। उन्होंने टी-20 विश्व कप में भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है, जिसमें कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डंस स्टेडियम में होने वाला मैच भी एक है। उनकी मांग थी कि उनसे संबंधित क्रिकेट मैच, ठीक पाकिस्तान की तरह, तटस्थ देश श्रीलंका स्थानांतरित किया जाए।

फिर, यहां एक विचार है। संभवतः बांग्लादेश संबंधित मैचों को दक्षिण भारत में स्थानांतरित कर दिया जाता, जहां पर बंगाली दर्शक कम होते हैं। संभव है उन्हें अमिताव घोष द्वारा पिछले दशकों में, बहुत डूबकर लिखे तीन नॉवेल (द शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड, गन आइलैंड) के झकझोर देने वाले विषय-वस्तु का इतनी गहराई से अहसास न हो। अब शीर्ष भाजपा नेतृत्व के लिए समय आ गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से राब्ता बनाएं -और बीएनपी भी यही करे– हालांकि बीएनपी प्रमुख, तारिक रहमान, इन दिनों 12 फरवरी को होने वाले चुनावों की तैयारी के लिए रैलियों-बैठकों के साथ देश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आख़िरकार, यदि आरएसएस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बात कर सकती है, तो शेष कुछ भी संभव है।

यह विचार दोनों पक्षों के लिए है कि अपना चेहरा बचाएं, ठंडे दिमाग वालों को वार्ता करने दें ताकि गर्म दल वाले अवसर हथिया न सकें। हमारे द्विपक्षीय इतिहास में इससे भी बदतर घटित हुआ है। वास्तव में, 1971 में बना उत्साह लंबे समय तक टिका नहीं; चार साल से भी कम अवधि में, 15 अगस्त, 1975 को, बांग्लादेशी फिर से बांग्लादेशियों का कत्ल कर रहे थे। वर्तमान में लौटते हुए। आज की कहानी अब मुस्तफिजुर रहमान और यहां तक कि उन शेख हसीना के बारे में और अधिक नहीं रही, जिन्होंने द प्रिंट को दिए अपने साक्षात्कार में आगामी बांग्लादेशी चुनावों में आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने को 'बदलाव का रूप धरा अधिनायकवाद' बताया है। यह तथ्य कि उन्होंने दिल्ली स्थित विदेशी संवाददाता क्लब को एक वॉयस मैसेज जारी किया है, उसमें भी मूल रूप से वही संदेश था। (ऐसा कहा जा रहा है कि उनका क्लब में खुद मौजूद न रहना या वीडियो संदेश जारी न करना, उनसे बनी सहमति का एक हिस्सा है)।

निस्संदेह, भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध -अगस्त 2024 में हसीना के तख्ता पलट और हाल ही में बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं की प्रतिशोध की भावना से की गई हत्याओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं- क्षति नियंत्रण तुरंत शुरू न करना बहुत नुकसानदायक होगा। एक शुरुआत हो चुकी है, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ढाका गए थे। पिछले नवंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान भारत में अपने समकक्ष अजीत डोभाल से मिलने दिल्ली आए थे।

दोनों तरफ दांव बहुत बड़ा लगा है। भारत को न केवल विभिन्न जनजातियों, धर्मों, कुलों और राजनीतिक दलों के मिश्रण वाले संवेदनशील उत्तर-पूर्व अंचल की सुरक्षा के लिए बल्कि पूर्वी दिशा के मुल्कों के साथ रिश्तों में हो रहे तेजी से बदलाव के बीच बांग्लादेश के साथ की जरूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। कई लोग हसीना के अहंकार-कुशासन का हवाला देते हुए कहते कि उन्हें इसलिए उखाड़ फेंका गया। यह भी उतना ही सच है कि भारत ने बहुत कुछ नजरअंदाज किया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि शेख हसीना और बीएनपी का आपस में हमेशा बैर रहा है। बीएनपी ने दो बार राष्ट्रीय चुनाव का बहिष्कार किया, जिससे घरेलू राजनीतिक कलह बढ़ गई।

लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, शेख हसीना भारत की पसंदीदा क्यों बनी रहीं, इसका कारण यह है कि वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष रहीं। वे हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने को महत्वपूर्ण समझती थीं, खुली वार्ता के अलावा सीमापारीय व्यापार के पक्ष में थीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के नेतृत्व वाले घातक लोगों को घुसने नहीं दिया। वे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में किस कदर नुकसान पहुंचा सकते थे कि उसके सामने धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कथानक दार्जिलिंग चाय और वॉटरक्रेस सैंडविच परोसने वाली किटी पार्टी की तरह लगता। उस विशाल हथियार जखीरे को कौन भूल सकता है जो संयोगवश तब मिला था जब तारिक की मां, दिवंगत खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं और जिसका उद्देश्य भारत के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में समस्या पैदा करना था?

आज की तारीख में शेख हसीना दिल्ली में हैं और भारत उन्हें कभी नहीं सौंपेगा –इतनी बात बांग्लादेश को समझनी होगी। बल्कि सराहना भी करनी होगी कि भारत अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ता, चाहे दांव पर कुछ भी क्यों न हो। चाहे न्यायाधिकरण उन्हें सौंपने करने की मांग 'मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी' ठहराकर करें।

सबसे महत्वपूर्ण, दोनों देशों के कुलीन वर्ग को यह अहसास होना चाहिए कि आज का भारत और बांग्लादेश कहीं अधिक युवा, कहीं अधिक आकांक्षी और महत्वाकांक्षी हैं। करीब 63 प्रतिशत बांग्लादेशी और 52 प्रतिशत भारतीय 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। वे अतीत का कटु बोझ ढोना पसंद नहीं करेंगे। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस वक्त तो वे पैदा भी नहीं हुए थे। वे जीवन में आगे बढ़ना और तरक्की करना चाहेंगे – न कि माथापच्ची में उलझे रहना। तो फिर, आगे का रास्ता यह है कि हसीना के मामले को इतर रखा जाए। भारत में उनकी मौजूदगी से द्विपक्षीय संबंधों को दूषित न होने दिया जाए। नए बांग्लादेश को समझना चाहिए कि भारत का विशाल आकार और उपस्थिति उसको वह असाधारण फायदा पहुंचाती है, जिसका मध्य स्तर की शक्तियां केवल सपना देख सकती हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो बेगम खालिदा के पुत्र तारिक एक महीने से भी कम समय में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। कुल मिलाकर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। अब दोनों पक्षों के लिए लकीर पार करने का समय आ गया है।

सही मायने में आज बांग्लादेश को भारत की जरूरत कहीं ज्यादा है। हो सकता है शी जिनपिंग का चीन तारिक के लिए आर्थिक मदद का बड़ा चेक काटकर दे, जैसा कि जिनपिंग ने 2016 में शेख हसीना के वक्त भी किया था और पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ना शुरू कर दे। लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान 2,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खस्ताहाल है कि उसने देश को चीन के हवाले कर रखा है। नैसर्गिक पड़ोसी भारत है। प्राकृतिक बाज़ार भारत है। स्वाभाविक साझेदार भी भारत है।

इसीलिए क्रिकेट नई शुरुआत करने का एक माध्यम बन सकता है। दोनों पक्षों के बीच तनाव को खत्म कर सकता है। लिट्टन दास का मिलन सूर्यकुमार यादव से होने दें। नागरिकों को खेलने दें।

प्रेरणा

सत्ता, युद्ध और करुणा के बीच मानवता की जीत

इतिहास के पन्नों में जब भी युद्धों और विजयों की चर्चा होती है, तो अक्सर तलवारों की चमक, तोपों की गूंज और सेनाओं की रणनीतियां केंद्र में रहती हैं। पर इतिहास की कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं, जो यह साबित करती हैं कि वास्तविक महानता केवल जीतने में नहीं, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय मूल्यों को बचाए रखने में है। मानवता का सम्मान वही कर सकता है, जिसके भीतर शक्ति के साथ करुणा और साहस के साथ संवेदना भी मौजूद हो। फ्रांस के प्रसिद्ध सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा एक प्रसंग इसी सत्य को गहराई से उजागर करता है। नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सफल सैन्य नेताओं में गिना जाता है। उनकी रणनीति, अनुशासन और साहस ने उन्हें अपराजेय बना दिया था। यूरोप के अनेक राज्य उनके विजय अभियानों के आगे झुक गए थे। लेकिन नेपोलियन की पहचान केवल एक विजेता के रूप में नहीं थी, बल्कि उनके शासन और युद्ध नीति में एक अलग दृष्टिकोण भी झलकता था। वे जीते हुए राज्यों को हमेशा नष्ट करने या अपने अधीन रखने के पक्षधर नहीं थे। कई बार वे पराजित राजाओं से वफादारी का आश्वासन लेकर उनका राज्य उन्हें वापस सौंप देते थे। यह नीति उनके राजनीतिक कौशल के साथ-साथ उनके भीतर मौजूद आत्मविश्वास और उदारता को भी दर्शाती थी।

ऐसी ही एक घटना में नेपोलियन ने एक पराजित राजा को उसका राज्य पुनः सौंप दिया। उस राजा ने नेपोलियन के सामने निष्ठा का वचन दिया था। लेकिन समय बीतते ही उसने इस वचन को भुला दिया और नेपोलियन के शत्रुओं से जा मिला। यह विश्वासघात किसी भी शासक या सेनापति के लिए असहनीय होता। यह केवल सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि सम्मान और विश्वास पर किया गया आघात भी था। नेपोलियन ने इसे गंभीर चुनौती के रूप में लिया और उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करने का निर्णय किया। नेपोलियन की विशाल सेना जैसे ही राजधानी की ओर बढ़ी, पूरे राज्य में भय और अफरा-तफरी फैल गई। सैनिकों की अनुशासित टुकड़ियां, भारी हथियार और तोपें देखकर राजा समझ गया कि अब बचना आसान नहीं है। वह अपने परिवार के साथ जंगलों की ओर भाग निकला। लेकिन युद्ध की हड़बड़ी और भय के बीच एक करुण भूल हो गई। राजा का एक बीमार राजकुमार महल में ही छूट गया। उसकी असहाय स्थिति का किसी को ध्यान नहीं रहा। युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी और नेपोलियन ने राजमहल को तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया। तोपों की पहली गर्जना के साथ ही राजधानी में आतंक फैल गया। महल की दीवारें कांपने लगीं। भीतर मौजूद बीमार राजकुमार भय और दर्द से इधर-उधर भागने लगा। वह न तो युद्ध का दोषी था और न ही किसी साजिश का हिस्सा। वह केवल परिस्थितियों का शिकार एक निर्दोष बालक था। इसी बीच, कुछ सैनिकों को उसके वहां मौजूद होने की जानकारी मिली। शायद सैनिकों के भीतर भी मानवता अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। उन्होंने इस सूचना को तुरंत अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया और बात नेपोलियन तक जा पहुंची। यह वह क्षण था, जिसने नेपोलियन के व्यक्तित्व का एक अलग ही पक्ष सामने रखा। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि महल के भीतर एक बीमार और निर्दोष राजकुमार मौजूद है, उन्होंने बिना एक पल गंवाए गोलाबारी रोकने का आदेश दे दिया। युद्ध के बीच अचानक तोपें शांत हो गईं। सैनिकों के चेहरों पर आश्चर्य और भ्रम था। जो सेना कुछ क्षण पहले पूरी ताकत से आक्रमण कर रही थी, वह एक आदेश पर थम गई। तोपों की आवाज बंद होते ही एक वरिष्ठ सेनापति ने नेपोलियन से सवाल किया। उसके अनुसार यह निर्णय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने वाला था और युद्ध के स्थापित नियमों के भी खिलाफ था। शत्रु की राजधानी पर हमला रोकना रणनीतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता था। सेनापति को लगा कि इस करुणा ने युद्ध की गति और सेना के उत्साह को नुकसान पहुंचाया है।

नेपोलियन का उत्तर इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है। उन्होंने सेनापति की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वे मानते हैं कि सैनिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन यदि गोलाबारी जारी रहती तो मानवता का भी अपमान होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीरता का अर्थ केवल शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि निर्दोष जीवन की रक्षा करना भी वीरों का धर्म है। उनके शब्दों में एक ऐसी नैतिक शक्ति थी, जिसने युद्ध की कठोरता के बीच मानवता को सर्वोपरि स्थान दिया।

यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली वीरता क्या होती है। क्या शक्ति का प्रदर्शन ही वीरता है, या शक्ति के होते हुए भी करुणा दिखा पाना उससे बड़ा साहस है? युद्ध का मैदान आमतौर पर संवेदनाओं के लिए जगह नहीं छोड़ता, लेकिन नेपोलियन का यह निर्णय साबित करता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक विवेक को जीवित रखा जा सकता है। मानवता का सम्मान केवल युद्ध तक सीमित मूल्य नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में उतना ही प्रासंगिक है। जब सत्ता और शक्ति संवेदना से अलग हो जाती हैं, तब वे अत्याचार और विनाश का कारण बनती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन शासकों ने केवल बल और भय के सहारे शासन किया, वे भले ही कुछ समय के लिए सफल रहे हों, लेकिन उन्हें स्थायी सम्मान नहीं मिला। इसके विपरीत, जिन नेताओं ने अपने निर्णयों में मानवता और नैतिकता को महत्व दिया, वे सदियों तक स्मरणीय बने। आज के समय में यह कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, हिंसा और संघर्ष जारी हैं। अक्सर इन संघर्षों में सबसे अधिक पीड़ा निर्दोषों को सहनी पड़ती है। ऐसे में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम शक्ति के साथ करुणा को जोड़ पा रहे हैं या नहीं। मानवता का सम्मान ही वह मूल्य है, जो सभ्यता और बर्बरता के बीच की रेखा तय करता है। नेपोलियन का यह निर्णय यह भी सिखाता है कि करुणा कमजोरी नहीं होती।

भावनाओं के नियमन से उजाले की पगडंडी

पहाड़ों या घने जंगलों में लोगों के सतत आवागमन से कुछ रास्ते स्वतः ही बन जाते हैं। इन्हें हम पगडंडी कहते हैं। इनमें कुछ पगडंडियां सुगम होती हैं, जिन पर चलना आसान होता है। वहीं कुछ इतनी संकरी और उबड़खाबड़ होती हैं कि उन पर चलना एक चुनौती बन जाता है। कुछ पगडंडियां हमें हमारे गंतव्य स्थल तक पहुंचाती हैं तो कुछ भटकाव की भूल-भुलैया में छोड़ देती हैं।

दरअसल, मानवीय भावनाओं का संसार भी कुछ ऐसी ही पगडंडियों से बना होता है। प्रसन्नता की पगडंडी हमें खिले हुए फूलों जैसी दुनिया में ले जाती है, जहां सौंदर्य के रिश्तों की अनूठी छटा बिखरी होती है। वहीं दुख की राह किसी घने अंधेरे जंगल में ले जाती है, जहां केवल निराशा और हताशा का वास होता है। भय की राहों पर आशंकाओं के कांटे बिछे होते हैं, तो क्रोध की राह अंगारों से दहक रही होती है।

यहां प्रश्न उठता है कि आखिर भावनाओं की इन पगडंडियों का उद्गम स्थल कहां है? कहां से यह कारवां शुरू होता है? आधुनिक विज्ञान मानता है कि भावनाओं का जन्म हमारे मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में स्थित 'लिम्बिक सिस्टम' भावना का केंद्र होता है। इसमें विशेष रूप से अमिगडाला की भूमिका प्रमुख होती है, जो भय, क्रोध और आनंद जैसी तत्काल भावनाओं को जन्म देता है। साथ ही डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सिटोसिन जैसे रसायनों से भावनाओं का निर्धारण करता है।

Advertisement

मनोविज्ञान इस विमर्श को थोड़ा सूक्ष्म रूप में परिभाषित करता है। इसके अनुसार भावनाएं हमारे विचारों से जन्म लेती हैं। अवचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं, पुरानी यादें और गहरे संस्कार सुप्त अवस्था में रहते हैं, जो अचानक किसी उत्प्रेरक के मिलने पर भावना के रूप में फूट पड़ते हैं। कई बार किसी घटना के प्रति हमारा नजरिया भी भावनाओं को जन्म देता है। भारतीय दर्शन और अध्यात्म इसे और गहराई से देखता है। हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है कि भावनाओं का असली घर हमारा चित्त है, जो एक गहरे सरोवर की तरह है। इस सरोवर की तलहटी में हमारे पुराने संस्कार और वृत्तियां जमा रहती हैं। जैसे शांत सरोवर में कंकड़ फेंकने से लहरें उठती हैं, वैसे ही संस्कारों के इस मानस सरोवर में जब बाहरी दुनिया का कोई विषय स्पर्श करता है, तो जो कंपन होता है, वही भावनाएं हैं और यहीं से जन्म होता है -भावनाओं की पगडंडी का।

भावनाओं की पगडंडी के निर्माण के संदर्भ में श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 2 के श्लोक 62 में भी एक श्लोक मिलता है— 'पहले मन में किसी विषय का चिंतन होता है, चिंतन से उस विषय में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और जब कामना पूरी नहीं होती या उसमें बाधा पड़ती है, तो क्रोध जन्म लेता है। और इस तरह क्रोध की भावना की पगडंडी का निर्माण होता है।'

दरअसल, इन पगडंडियों पर चलते हुए अक्सर हम दिशा-भ्रमित हो जाते हैं। भावनाओं की जटिलता से निपटने के लिए अक्सर हमारी सहज प्रतिक्रिया उनके 'दमन' की हो जाती है। बचपन से ही हमें 'क्रोध न करने' या 'आंसू रोकने' का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम समझते हैं कि भावनाओं का दमन कर देने से हम संयमित कहलाएंगे। जबकि सच्चाई यह है कि भावनाओं का जबरन दमन, बहते पानी पर कच्चा बांध बनाने जैसा है, जिसमें पानी क्षणिक रूप से रुक सकता है, परंतु उसका बढ़ता दबाव अंततः किसी घातक मानसिक विस्फोट का कारण बनता है। तो फिर अप्रिय भावनाओं से निपटने का समाधान अगर दमन नहीं है तो दूसरा सही मार्ग क्या है? उत्तर है- 'उदात्तीकरण'। यहां यह समझना जरूरी है कि भावना, मूल रूप से, केवल एक 'ऊर्जा' है। विज्ञान का नियम है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक इसी तरह, हमारी भावनाएं न अच्छी होती हैं, न बुरी; वे सिर्फ एक शक्ति हैं जो प्रवाहित होना जानती हैं। जीवन की कला इस पगडंडी को अवरुद्ध करने में नहीं, बल्कि इसकी दिशा ऊंचाई की ओर मोड़ देने में है। जब भावना की दिशा बदलती है, तो वही ऊर्जा जो पतन का कारण बन सकती थी, उत्थान का आधार बन जाती है।

इतिहास गवाह है कि जब-जब मनुष्य ने अपनी भावनाओं की दिशा बदली है, तब-तब साधारण व्यक्ति महामानव बना है। तुलसीदास जी का पत्नी के प्रति घोर 'मोह', उसके कर्कश व्यवहार से उनके चिंतन की दिशा बदलते ही शाश्वत 'भक्ति' में परिणत हो गया।

वस्तुतः भावनाएं हमारे अस्तित्व का शाश्वत सत्य हैं। उनसे मुख मोड़ना, उनसे भयभीत होना या उन्हें शत्रु मानकर लड़ना व्यर्थ है। जो पगडंडी गहन अंधकार की ओर जाती है, सजगता और दिशा बदलते ही, वही प्रकाश के शिखर तक भी पहुंचा सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम आवेग में बहने के बजाय, उस ऊर्जा को सृजन में रूपांतरित कर सकें। निःसंदेह, जीवन की सार्थकता भावनाओं से पलायन करने में नहीं, बल्कि उन्हें उस पगडंडी में रूपांतरित कर देने में है, जो अंतर्मन के अंधेरे से निकलकर शाश्वत प्रकाश की ओर जाती हो।

अभियान

श्रद्धा, साधना और संकल्प से श्रीकृष्ण कृपा का अनुभव

भारतीय सनातन परंपरा में मंत्र साधना को आत्मशुद्धि और जीवन परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। मंत्र केवल ध्वनि या शब्दों का संयोजन नहीं होते, बल्कि वे चेतना को जाग्रत करने वाली दिव्य ऊर्जा होते हैं। जब किसी मंत्र का जाप नियम, संयम और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है, तो वह साधक के जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। आज के समय में, जब मनुष्य मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, असुरक्षा, भय और अनिश्चित भविष्य से जूझ रहा है, तब भक्ति और साधना ही वह मार्ग बनती है, जो भीतर से टूट चुके मन को स्थिरता और आशा प्रदान करती है। इसी संदर्भ में वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए भगवान श्रीकृष्ण के एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र की चर्चा विशेष महत्व रखती है।

प्रेमानंद महाराज का मानना है कि भगवान श्रीकृष्ण करुणा, प्रेम और करुणामय लीला के प्रतीक हैं। वे केवल द्वापर युग के एक अवतार नहीं, बल्कि आज भी अपने भक्तों के जीवन में उसी तरह सक्रिय हैं, जैसे युगों पहले थे। महाराज कहते हैं कि श्रीकृष्ण तक पहुंचने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त है पूर्ण समर्पण। जब तक मनुष्य आधे मन से भक्ति करता है, तब तक उसे पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे मंत्र का उल्लेख किया है, जिसका निरंतर 21 दिनों तक जाप करने से जीवन के अनेक क्लेश स्वतः शांत होने लगते हैं।

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होने के साथ-साथ कठिन भी है, क्योंकि इसमें केवल मुख से जाप पर्याप्त नहीं है। इसमें मन, भाव और चेतना—तीनों का एक साथ जुड़ना आवश्यक है। साधना के समय साधक के मन में केवल भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का स्मरण होना चाहिए। संसार की चिंताएं, इच्छाएं, भय और कल्पनाएं यदि मन में आती रहें, तो मंत्र की पूर्ण शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। यही कारण है कि यह मंत्र साधक की आंतरिक शुद्धि की भी परीक्षा लेता है।

प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया यह मंत्र है—

"ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ॥"

महाराज बताते हैं कि यह मंत्र अपने आप में संपूर्ण श्रीकृष्ण तत्व को समेटे हुए है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण के चार प्रमुख नामों—कृष्ण, वासुदेव, हरि और परमात्मा—का एक साथ स्मरण किया गया है। 'कृष्ण' नाम आकर्षण और आनंद का प्रतीक है, 'वासुदेव' भगवान के अवतार स्वरूप को दर्शाता है, 'हरि' दुखों और पापों को हर लेने वाले तत्व को प्रकट करता है और 'परमात्मा' यह संकेत देता है कि श्रीकृष्ण केवल एक रूप नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना हैं। जब साधक इन चारों नामों का एक साथ जाप करता है, तो मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।

इस मंत्र का भावार्थ साधक को शरणागति की भावना में ले जाता है। इसका अर्थ है कि मैं वासुदेव के पुत्र भगवान श्रीकृष्ण को नमन करता हूं, जो हरि स्वरूप हैं, जो परमात्मा हैं और जो शरण में आए हुए भक्तों के समस्त दुखों और क्लेशों का नाश करते हैं। जो गोविंद हैं, अर्थात समस्त सृष्टि का पालन करने वाले हैं, उन्हें मैं बार-बार प्रणाम करता हूं। यह भाव साधक के अहंकार को धीरे-धीरे समाप्त करता है और उसे ईश्वर के चरणों में झुकना सिखाता है।

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इस मंत्र का सबसे पहला प्रभाव साधक के मन पर पड़ता है। 21 दिनों तक नियमित जाप करने से मानसिक अशांति, चिंता और भय में कमी आने लगती है। जो लोग निरंतर तनाव, बेचैनी, नकारात्मक विचारों या अवसाद से जूझ रहे हैं, उन्हें इस मंत्र से भीतर से शांति का अनुभव होने लगता है। मन धीरे-धीरे स्थिर होता है और विचारों की उथल-पुथल कम होने लगती है। यह मंत्र साधक के भीतर एक ऐसा भाव उत्पन्न करता है, जिससे वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना शुरू करता है।

इस मंत्र की साधना से आध्यात्मिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और नियम के साथ इस मंत्र का जाप करता है, तो उसकी चेतना भौतिक स्तर से ऊपर उठने लगती है। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि श्रीकृष्ण हर क्षण उसके साथ हैं। यह अनुभूति जीवन के सबसे बड़े भय—असुरक्षा—को समाप्त कर देती है। जब भीतर से भय समाप्त होता है, तब जीवन की समस्याएं स्वतः छोटी लगने लगती हैं।

पारिवारिक जीवन में कलह और तनाव आज लगभग हर घर की सच्चाई बन चुके हैं। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि इस मंत्र का प्रभाव पारिवारिक वातावरण पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो लोग घर में निरंतर विवाद, गलतफहमी या रिश्तों में कटुता का अनुभव कर रहे हैं, वे इस मंत्र के प्रभाव से अपने व्यवहार में परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। जब व्यक्ति स्वयं शांत और संतुलित होता है, तो उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। धीरे-धीरे घर में प्रेम, धैर्य और सामंजस्य का वातावरण बनने लगता है।

महाराज यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस मंत्र की साधना कोई तांत्रिक प्रयोग या चमत्कारिक उपाय नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसमें साधक को अपने जीवन की दिनचर्या और विचारों में भी सात्त्विकता लानी होती है। मंत्र जाप के लिए प्रातः स्नान के बाद या सायंकाल गोधूलि वेला को श्रेष्ठ माना गया है। इस समय वातावरण में स्वाभाविक शांति होती है, जो साधना में सहायक होती है। स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए, जहां साधक बिना व्यवधान के ध्यान कर सके। मंत्र जाप के लिए तुलसी की माला का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए तुलसी माला से कम से कम 108 बार मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। जाप प्रारंभ करने से पहले साधक को भगवान श्रीकृष्ण के समक्ष अपनी समस्या या मनोकामना को विनम्र भाव से रखना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि वह 21 दिनों तक इस साधना को पूरी निष्ठा के साथ करेगा। संकल्प साधना को दिशा और दृढ़ता प्रदान करता है।

प्रेमानंद महाराज यह भी कहते हैं कि इस साधना में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। कई लोग कुछ ही दिनों में चमत्कार की अपेक्षा करने लगते हैं, लेकिन यह मंत्र साधक की परीक्षा लेता है। इसका उद्देश्य केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि साधक के भीतर विश्वास, समर्पण और स्थिरता का विकास करना है। कई बार परिवर्तन बाहरी रूप में तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर गहराई से कार्य करता रहता है।

यह मंत्र साधक को यह भी सिखाता है कि जीवन में हर दुख का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जब व्यक्ति श्रीकृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब वह परिस्थितियों को बदलने की चिंता छोड़कर स्वयं को बदलने की दिशा में बढ़ता है। यही इस मंत्र की वास्तविक शक्ति है। यह साधक को आत्मबल देता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया

महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने इस पावन अवसर पर सभी रेलकर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई दीं

पहली तस्वीर में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। दूसरी तस्वीर में श्री गुप्ता उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए तथा अंतिम तस्वीर में महाप्रबंधक मुंबई के महालक्ष्मी स्पोर्ट्स ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सामारोहिक परेड का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पश्चिम रेलवे पर 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मुंबई के महालक्ष्मी स्पोर्ट्स ग्राउंड में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महाप्रबंधक ने औपचारिक परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च-पास्ट की सलामी भी ली।श्री गुप्ता ने इस गरिमामय अवसर पर उपस्थित रेलकर्मियों एवं उनके परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए सभा को संबोधित किया। समारोह के आरंभ में महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता का स्वागत पश्चिम रेलवे के आईजी सह प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अजय सदानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती नीता गुप्ता, पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, प्रमुख विभागाध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने अपने गणतंत्र दिवस संदेश में पश्चिम रेलवे द्वारा हाल ही में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया। महाप्रबंधक ने वर्ष 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित दक्षता शील्ड की सर्वाधिक संख्या प्राप्त करने पर सम्पूर्ण पश्चिम रेलवे टीम की प्रशंसा की। अपने संबोधन के समापन पर श्री गुप्ता ने सभी कर्मचारियों से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नवोन्मेष, नई ऊर्जा और समर्पण के साथ और अधिक परिश्रम करने का आह्वान किया।

फोटो कैप्शनःपश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती नीता गुप्ता को जगजीवन राम अस्पताल को उपयोगी वस्तुएँ दान करते हुए दिखाई दे रही हैं।

श्री विनीत ने बताया कि इस शुभ अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती नीता गुप्ता द्वारा पश्चिम रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल (JRH) में मरीजों के उपयोग हेतु स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन केतली दान की गईं, जिन्हें पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. अतुल शर्मा को सौंपा गया।

इस कार्यक्रम के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा डॉग स्क्वाड शो का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर देशभक्ति गीतों एवं नृत्य प्रस्तुतियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

भारत- ईयू एफटीए, माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप में एक बड़ी कामयाबी; निर्यात प्रतिस्पर्धा को बदलने और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के एकीकरण को गहरा करने के लिए तैयार: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

नई दिल्ली; 27 जनवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) ने भारत-यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता (भारत- ईयू एफटीए) के ऐतिहासिक ऐलान के बाद, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप, दूर की स्ट्रेटेजिक सोच और फैसले लेने वाली डिप्लोमेसी की दिल से तारीफ़ की है। इस ऐतिहासिक समझौते का ऐलान आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-ईयू समिट में मिलकर किया। भारत - ईयू एफटीए का पूरा होना भारत की वैश्विक इकोनॉमिक यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह व्यापार से होने वाली ग्रोथ, इकोनॉमिक सुधारों और वैश्विक एकीकरण के लिए भारत सरकार के पक्के प्रतिबद्धता का सबूत है। यह समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन को भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर मज़बूत करता है, जो खुले बाज़ार, पहले से तय और सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध हैं। फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह 2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से सरकार के मज़बूत राजनीतिक इरादे के साथ लगातार, नतीजे पर आधारित बातचीत का नतीजा है, जो एक संतुलित, मॉडर्न और नियमों पर आधारित इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाने के साझा नज़रिए को दिखाता है।

यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। वित्त वर्ष 2024–25 में, भारत - ईयू का वस्तु का आपसी व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (136.54 बिलियन डॉलर) था, जिसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये (75.85 बिलियन डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ रुपये (60.68 बिलियन डॉलर) का इंपोर्ट शामिल था। सेवा क्षेत्र में व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (83.10 बिलियन डॉलर) तक पहुँच गया। भारत और ईयू मिलकर दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हैं, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा हैं—यह एक ऐसा अवसर है जिसे भारत सरकार ने इस बदलाव लाने वाले एग्रीमेंट के ज़रिए स्ट्रेटेजिक तरीके से खोला है।

श्री रल्हन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के डायनैमिक और रिफॉर्म-ओरिएंटेड लीडरशिप में भारत- ईयू एफटीए का सफल होना एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है, जो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ाएगा और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देगा। यह एग्रीमेंट भारतीय निर्यातकों के लिए वस्तु और सेवा क्षेत्र में, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स, एमएसएमई, महिला एंटरप्रेन्योर्स, कारीगरों और युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए पहले कभी नहीं देखा गया मार्केट एक्सेस खोलता है—जो सरकार के इनक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा के मुख्य फोकस एरिया हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 33 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत तक टैरिफ खत्म होने से, एफटीए टेक्सटाइल, कपड़े, लेदर, फुटवियर, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, मरीन प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल जैसे खास सेक्टर को तुरंत और ठोस फायदा देगा। इन फायदों से ज़्यादा निर्यात, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और वैश्विक व्यापार में जमीनी स्तर पर मजबूत भागीदारी होगी, जिससे निर्यात से होने वाली खुशहाली के सरकार के विजन को मजबूती मिलेगी। इस समझौते में वस्तु और सेवा क्षेत्र का व्यापार, ओरिजिन के नियम, कस्टम में आसानी, व्यापार उपचारों और डिजिटल व्यापार और एमएसएमई जैसे उभरते हुए सेक्टर पूरी तरह से शामिल हैं। इसमें नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत सिस्टम शामिल हैं – जो बेहतर रेगुलेटरी सहयोग, ट्रांसपेरेंट एसपीएस उपायों और आसान कस्टम प्रोसेस के जरिए ईयू रेगुलेटर्स के साथ सरकार के प्रोएक्टिव जुड़ाव का नतीजा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सोच-समझकर और कोटा- आधारित लिबरलाइजेशन से ईयू मैन्युफैक्चरर्स को भारत में एडवांस्ड मॉडल पेश करने की इजाजत मिलेगी, साथ ही सरकार के 'मेक इन इंडिया'और 'आत्मनिर्भर भारत'पहल के साथ जुड़े भविष्य के मौके भी बनेंगे।

भारतीय उपभोक्ताओं को हाई-टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तक बेहतर एक्सेस और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से फायदा होने की उम्मीद है। चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड्स के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस के साथ एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा, जबकि सरकार ने डेयरी और अनाज जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को समझदारी से सुरक्षित रखा है, जिससे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। एफटीए आईटी/आईटीईएस, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और दूसरी बिजनेस सर्विसेज सहित सर्विसेज में कमर्शियली सार्थक प्रतिबद्धता देता है। 144 ईयू सब-सेक्टर्स में अनुमानित मार्केट एक्सेस भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अवसरों को काफी बढ़ाएगा, जबकि रेसिप्रोकल एक्सेस भारत में हाई-टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। प्रोग्रेसिव मोबिलिटी प्रोविजन्स भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वैश्विक अवसरों को प्राप्त करने के लिए सरकार की लगातार कोशिशों को दिखाते हैं, जिसमें शॉर्ट-टर्म बिजनेस ट्रैवल, इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस सप्लायर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स और डिपेंडेंट्स के लिए काम के अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर्स को ईयू सदस्य देशों में अपने टाइटल के तहत काम करने की मान्यता दिलाई है, जहाँ ऐसे तरीकों को रेगुलेट नहीं किया जाता है - यह एक महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक उपलब्धि है जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह समझौता टीआरआईपीएस के तहत बौद्धिक संपदा सुरक्षा को मजबूत करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को मान्यता देता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें सीबीएएम कंप्लायंस से संबंधित सहायता भी शामिल है।

श्री रल्हन ने दोहराया कि भारत- ईयू एफटीए, सरकार के हाल ही में ब्रिटेन और ईएफटीए के साथ हुए एफटीए के साथ मिलकर, भारतीय निर्यातकों के लिए पूरे यूरोपीय बाजार को प्रभावी ढंग से खोलता है, जो भारत की व्यापार कूटनीति में एक रणनीतिक सफलता है। यह ऐतिहासिक समझौता 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, और भारत को एक लचीले, प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी वैश्विक व्यापार नेता के रूप में स्थापित करता है।

भारत-ईयू एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव में एक नए युग की शुरुआत करता है, जो भारत सरकार की रणनीतिक स्पष्टता, बातचीत की ताकत और दीर्घकालिक विजन को दर्शाता है - 27-सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है, साथ ही भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नींव रखता है।

सोना वायदा में 2763 रुपये और चांदी वायदा में 27827 रुपये का अधिक ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा 44 रुपये फिसला

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 431942.41 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 91733.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 340187.74 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 45400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4547.63 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 80393.72 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 158674 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159820 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 157500 रुपये पर पहुंचकर, 156037 रुपये के पिछले बंद के सामने 2763 रुपये या 1.77 फीसदी बढ़कर 158800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 741 रुपये या 0.55 फीसदी की तेजी के संग 135935 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 90 रुपये या 0.53 फीसदी की तेजी के संग 16996 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी फरवरी वायदा 157478 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159899 रुपये और नीचे में 157478 रुपये पर पहुंचकर, 2481 रुपये या 1.58 फीसदी की तेजी के संग 159153 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 164499 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 167499 रुपये और नीचे में 164453 रुपये पर पहुंचकर, 163137 रुपये के पिछले बंद के सामने 3334 रुपये या 2.04 फीसदी की तेजी के संग 166471 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 339824 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 364821 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 339824 रुपये पर पहुंचकर, 334699 रुपये के पिछले बंद के सामने 27827 रुपये या 8.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 362526 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 27261 रुपये या 8.03 फीसदी की बढ़त के साथ 366550 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 27305 रुपये या 8.05 फीसदी की तेजी के संग 366624 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। मेटल वर्ग में 5578.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 3.45 रुपये या 0.26 फीसदी की मजबूती के साथ 1319.95 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 6.5 रुपये या 2.06 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 322.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.55 फीसदी की मजबूती के साथ 319.8 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 25 पैसे या 0.13 फीसदी टूटकर 191.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5266.44 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5570 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5623 रुपये और नीचे में 5475 रुपये पर पहुंचकर, 44 रुपये या 0.78 फीसदी औंधकर 5586 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 37 रुपये या 0.66 फीसदी की गिरावट के साथ 5591 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 332 रुपये के भाव पर खूलकर, 348.5 रुपये के दिन के उच्च और 332 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 328.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 18.6 रुपये या 5.66 फीसदी की तेजी के संग 347.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 18.2 रुपये या 5.53 फीसदी की तेजी के संग 347.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 91733.66 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 340187.74 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 80393.72 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 45400 पॉइंट के स्तर पर

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 1029.8 रुपये पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.12 फीसदी की तेजी के संग 1026.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 38491.19 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 41902.53 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4502.73 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 339.54 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 38.69 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 679.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 879.90 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 4371.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 12.07 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20338 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 101976 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 40486 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 588427 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 66014 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14212 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39403 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99532 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19552 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 21873 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 44500 पॉइंट पर खूलकर, 45407 के उच्च और 44500 के नीचले स्तर को छूकर, 1599 पॉइंट बढ़कर 45400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 42.3 रुपये की गिरावट के साथ 234.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 13.55 रुपये की बढ़त के साथ 40.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 161000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 600 रुपये की गिरावट के साथ 113 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 332000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 22549.5 रुपये की बढ़त के साथ 30859.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.53 रुपये की बढ़त के साथ 35.96 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 10.82 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 11.3 रुपये की बढ़त के साथ 205 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.1 रुपये की गिरावट के साथ 13.7 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1195 रुपये की गिरावट के साथ 116.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 257000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 19.5 रुपये की बढ़त के साथ 20 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.55 रुपये की गिरावट के साथ 7.75 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.83 रुपये की बढ़त के साथ 5.8 रुपये हुआ।

कस्तूरी मेटल कंपोजिट का आईपीओ निवेशकों के लिए खुला, तीन फरवरी को SME प्लेटफॉर्म पर संभावित लिस्टिंग

नई दिल्ली। स्टील फाइबर उत्पादों के निर्माण से जुड़ी कस्तूरी मेटल कंपोजिट लिमिटेड ने पूंजी बाजार में कदम रखते हुए मंगलवार से अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया है। कंपनी इस इश्यू के जरिए कुल 17.61 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। निवेशक इस आईपीओ में 29 जनवरी तक बोली लगा सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े जानकारों के मुताबिक, इस इश्यू का अलॉटमेंट 30 जनवरी को तय किया जाएगा, जबकि 2 फरवरी को शेयर निवेशकों के डीमैट खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो कस्तूरी मेटल कंपोजिट के शेयर 3 फरवरी को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 61 से 64 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इश्यू में एक लॉट में 2,000 शेयर रखे गए हैं, यानी न्यूनतम निवेश के लिए निवेशकों को 1,28,000 रुपये लगाने होंगे। रिटेल निवेशकों को अधिकतम दो लॉट यानी 4,000 शेयरों के लिए आवेदन करने की अनुमति है, जिसके लिए अधिकतम 2,56,000 रुपये का निवेश करना होगा।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन भावनगर मंडल द्वारा 77वाँ गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार, 26 जनवरी 2026 को पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा संचालित बाल मंदिर एवं किड्स हट स्कूलों में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी वर्मा तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा तिरंगा ध्वज फहराया गया।

कार्यक्रम के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की पदाधिकारी सदस्याएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति के गीतों, गतिविधियों एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रप्रेम की भावना का सुंदर प्रदर्शन किया।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सेवा एवं संवेदना के भाव को आगे बढ़ाते हुए मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर परा में भर्ती 18 मरीजों एवं 10 सफाई कर्मचारियों को WRWWO की अध्यक्ष महोदया एवं संगठन की अन्य सदस्याओं के कर-कमलों से उपहार एवं फल वितरित किए गए। यह आयोजन संगठन की सामाजिक प्रतिबद्धता एवं मानवीय मूल्यों को दर्शाने वाला रहा।

इस अवसर पर WRWWO भावनगर की अध्यक्ष महोदया ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ाव, सहयोग और सेवा भावना को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महिला कल्याण संगठन की सभी सदस्याओं का योगदान सराहनीय रहा।

भावनगर रेलवे मंडल पर पूरे उत्साह के साथ मनाया गया 77वाँ गणतंत्र दिवस

भावनगर रेलवे मंडल पर 26 जनवरी, 2026 (सोमवार) को 77वाँ गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री वर्मा ने रेलवे स्टेडियम भावनगर परा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा झंडे को सलामी दी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार मंडल सुरक्षा आयुक्त (रेलवे सुरक्षा बल) श्री प्रेमनाथ राय की आगवानी में भारत स्काउट एण्ड गाइड, सेंट जॉन एम्ब्युलेंस, नर्सिंग युनिटों व रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने इस अवसर पर परेड की मनोहर झांकी प्रस्तुत की, जिसका निरीक्षण मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा किया गया। उसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक ने इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के संदेश का वाचन किया तथा उन्होंने

समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों एवं नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित बाल मंदिर और कीड्स हट तथा पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय भावनगर परा के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर सुख, शांति एवं समृद्धि के प्रतीक तिरंगे रंगों के गुब्बारों को गगन में मुक्त कर एकता, आशा और उज्जवल भविष्य का सशक्त संदेश दिया गया।

इस अवसर पर मंडल कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन एवं नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अन्त में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बानाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 कर्मचारियों को भी मंडल रेल प्रबंधक द्वारा नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण समिति-भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले नन्हें मुन्हें बच्चों की काफी प्रशंसा की। भावनगर रेलवे मंडल के सभी स्टेशनों, हेल्थयूनिटों और कोचिंग डिपो में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

आम बजट 2026-27 की अंतिम तैयारी तेज, नॉर्थ ब्लॉक में हलवा बनते ही शुरू हुई उलटी गिनती

नई दिल्ली। देश के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 की औपचारिक उलटी गिनती मंगलवार से शुरू हो गई, जब नॉर्थ ब्लॉक में पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर के साथ ही बजट निर्माण की प्रक्रिया अपने सबसे निर्णायक और गोपनीय चरण में प्रवेश कर गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पारंपरिक आयोजन में हिस्सा लेकर बजट तैयार करने में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। हलवा समारोह के बाद बजट दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसे बजट की अंतिम तैयारी का प्रतीक माना जाता है।

रायसीना हिल्स स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित इस समारोह का विशेष महत्व इसलिए भी रहा क्योंकि वित्त मंत्रालय का बड़ा हिस्सा अब नए केंद्रीय सचिवालय परिसर, कर्तव्य भवन में स्थानांतरित हो चुका है। इसके बावजूद बजट छपाई की दशकों पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी नॉर्थ ब्लॉक को ही चुना गया। समारोह में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और बजट प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने इस दौरान बजट प्रेस का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि छपाई से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से पूरी की जाएं।

हलवा समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि बजट प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीयता और अनुशासन का प्रतीक भी है। इस समारोह के बाद वित्त मंत्रालय से जुड़े लगभग 60 से 70 अधिकारी और कर्मचारी 'लॉक-इन पीरियड' में प्रवेश कर जाते हैं। इस अवधि के दौरान ये अधिकारी मंत्रालय परिसर के भीतर ही रहते हैं और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। न तो वे परिसर से बाहर जा सकते हैं और न ही किसी से फोन या अन्य माध्यमों से संवाद कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बजट से संबंधित कोई भी संवेदनशील जानकारी समय से पहले सार्वजनिक न हो और बजट की गोपनीयता पूरी तरह बनी रहे। यह लॉक-इन अवधि तब तक जारी रहती है, जब तक वित्त मंत्री संसद में बजट भाषण पूरा नहीं कर देतीं।

सरकार ने साफ कर दिया है कि वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट भी पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में ही पेश किया जाएगा। इससे पहले के पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट की तरह इस बार भी बजट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांगें, वित्त विधेयक और अन्य सहायक दस्तावेज 'केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप' और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आम जनता तक पहुंचेंगे। डिजिटल बजट की यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि इससे बजट दस्तावेजों तक लोगों की आसान और त्वरित पहुंच भी सुनिश्चित होती है।

इस बजट को लेकर आर्थिक जगत, उद्योग, कारोबारी संगठनों, किसानों, मध्यम वर्ग और आम नागरिकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं, महंगाई के दबाव, रोजगार सृजन की जरूरत और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसी चुनौतियों के बीच यह बजट सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगा। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर देखने को मिल सकता है।

हलवा समारोह के साथ ही बजट की छपाई शुरू हो जाने का मतलब यह भी है कि अब बजट के आंकड़े और प्रस्ताव अंतिम रूप ले चुके हैं। बजट निर्माण में महीनों से जुटे अधिकारी अब अंतिम दस्तावेजों को आकार देने में लगे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अत्यंत सतर्कता और अनुशासन बरता जाता है, क्योंकि बजट से जुड़ी एक छोटी सी चूक भी बड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डाल सकती है।

परंपरा और आधुनिक तकनीक के इस अनोखे मेल के साथ केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। नॉर्थ ब्लॉक में बने हलवे के साथ न केवल बजट की छपाई शुरू हुई है, बल्कि देश की जनता के लिए नई आर्थिक उम्मीदों और नीतिगत संकेतों की घड़ी भी करीब आ गई है। अब सबकी निगाहें उस दिन पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री संसद के पटल पर बजट पेश कर देश को आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक तस्वीर से रूबरू कराएंगी।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके दवारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। प्रतापनगर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं रेल सुरक्षा बल ,भारत स्काउट व गाइड व सिविल डिफ़ेंस यूनिटों की सयुंक्त परेड का निरीक्षण किया और मार्च-पास्ट की सलामी ली।इस अवसर पर श्री राजू भडके ने सभी रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन भी किया। मंडल रेल प्रबंधक ने रेलकर्मियो के नाम अपने सन्देश में वडोदरा मंडल की उपलब्धिया का भी जिक्र किया और रेल सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर श्री अनवर हुसैन को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा "इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस" से सम्मानित किये जाने पर बधाई दी। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस अवसर पर संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं व सराहनीय कार्य के लिये 04 रेलकर्मियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा की अध्यक्षा डॉ कविता भडके ने निबंध/ चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता 19 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। आरपीएफ 'डॉग स्क्वॉड' द्वारा की गयी प्रस्तुति ने भी सभी का मन मोह लिया रेलकर्मियों द्वारा देश भक्ति पर आधारित व सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। इस शुभ अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्यक्षा डॉ कविता भडके व उनकी टीम, वडोदरा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री फ्रांसिस लोबो तथा रेलवे के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ रेल अधिकारी व कर्मचारी के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री तेजराम मीना ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। इसके बाद मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके व रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्यक्षा डॉ कविता भडके ने बाल मंदिर में जाकर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में बच्चो की प्रस्तुति को देखा।

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी ने 'स्वतंत्रता का मंत्र : वंदे मातरम' विषय पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की निर्माण यात्रा, उसके बदलते स्वरूप और इतिहास की रोचक प्रस्तुति के साथ जमाया अनूठा आकर्षण

▸▸ सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर गुजरात को गौरवान्वित किया

▸▸ 77वें गणतंत्र पर्व में इस वर्ष पहली बार 'साइलेंट वॉरियर्स' के रूप में पहचाने जाने वाले पशुओं ने भी परेड में हिस्सा लिया

नई दिल्ली : 'वंदे मातरम' एक मंत्र है, जो हर भारतीय में स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता की अलख जगाता है। 'वंदे मातरम' गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, इस विषय के प्रतिघोष के रूप में 'वंदे मातरम' शब्द की पृष्ठभूमि से ही शुरू हुई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बनने की यात्रा, उसका बदलता स्वरूप और इतिहास की रोचक प्रस्तुति 77वें गणतंत्र दिवस पर्व में गुजरात की झांकी का प्रमुख आकर्षण बना। इसके साथ ही, इस झांकी ने गुजरात के नवसारी में जन्मी तथा गुर्जर भूमि के अपने प्रसिद्ध साथी क्रांतिवीरों- श्यामजी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा के साथ विदेशी धरती से क्रांतिज्योत जगाने वालीं मैडम भीकाजी कामा द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज की यशोगाथा का वर्णन, जिस पर 'वंदे मातरम' लिखा है और 'चरखे' के माध्यम से स्वदेशी का मंत्र देने वाले महात्मा गांधी की स्मृति के साथ मौजूदा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के सुंदर समन्वय के माध्यम से एक अनूठी छाप छोड़ी।

झांकी के अगले हिस्से में वीरांगना मैडम भीकाजी कामा को उनके द्वारा डिजाइन किए हुए ध्वज के साथ दर्शाया गया था, जिस पर 'वंदे मातरम' लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर वर्ष 1907 में पेरिस में लहराया था। इस ध्वज को जर्मनी के स्टटगार्ट, बर्लिन की 'इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस' में भी फहराया गया था। मैडम कामा की ध्वज लहराती अर्ध-प्रतिमा के नीचे संविधान में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं में 'वंदे मातरम' लिखा हुआ था।

झांकी के दिल यानी मध्य हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज की निर्माण यात्रा, उसके बदलते स्वरूप और इतिहास को दिखाया गया। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1906 से, जब कलकत्ता (अब कोलकाता) के पारसी बागान में क्रांतिकारियों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने और स्वदेशी का आह्वान करते हुए पहली बार 'वंदे मातरम' लिखा हुआ ध्वज फहराया था। इसके बाद, 1907 में विदेशी धरती से भारतीय क्रांति की ज्योति जगाने वाली मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में ध्वज फहराया था, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। वर्ष 1917 में होमरूल आंदोलन के दौरान डॉ. एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक नया ध्वज फहराया। वहीं, वर्ष 1921 में बेजवाड़ा (अब विजयवाड़ा) में युवा क्रांतिवीर पिंगली वेंकैया ने एक नई डिजाइन का ध्वज बनाया और उसे गांधी जी को दिखाया। 1931 में पिंगली द्वारा तैयार किए गए ध्वज को लगभग स्वीकृति दे दी गई, जो तीन रंगों का बना था और उसके केंद्र में चरखा था। अंततः 22 जुलाई, 1947 को भारतीय संविधान सभा ने झंडे के केंद्र में चरखे की जगह धर्म चक्र के साथ तिरंगे को इसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की इस निर्माण यात्रा के साथ भारत की आजादी के महत्वपूर्ण आंदोलनों का भी इस झांकी में निदर्शन किया गया।

झांकी के अंतिम हिस्से में 'चरखे' के माध्यम से स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना को जागृत करने तथा स्वतंत्रता का आह्वान करने वाले महात्मा गांधी के शिल्प को एक विशाल धर्म चक्र के साथ दर्शाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के इन सशक्त मूल्यों को लगातार प्रोत्साहित करने का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को याद कर राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले, 'राष्ट्रीय शायर' की उपाधि से सम्मानित गुजराती रचनाकार झवेरचंद मेघाणी द्वारा रचित गीत 'कसुंबी नो रंग' की लय और ताल पर उत्साह बढ़ाते कलाकार झांकी को जीवंत और जानदार बना रहे थे।

गुजरात सरकार के सूचना विभाग की ओर से प्रस्तुत इस झांकी के निर्माण में सूचना एवं प्रसारण सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी, अपर निदेशक श्री अरविंद पटेल के मार्गदर्शन में संयुक्त सूचना निदेशक डॉ. संजय कचोट और उप सूचना निदेशक सुश्री भावना वसावा ने योगदान दिया।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की 13 झांकियों सहित कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की गईं। कर्तव्य पथ पर हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लगभग 2500 कलाकारों ने हिस्सा लिया। देश भर से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था।

परेड की शुरुआत 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' में एक गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हुई, जहां प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद, राष्ट्रपति सलामी मंच पर पहुंचीं और राष्ट्रगान हुआ तथा 21 तोपों की सलामी के साथ समारोह की औपचारिक शुरुआत हुई। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन यूनियन के दो वरिष्ठ नेता- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मौजूद रहे।

77वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष पहली बार 'साइलेंट वॉरियर्स' के रूप में पहचाने जाने वाले पशुओं ने भी परेड में हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत मंगोलियन प्रजाति के बेक्ट्रियन ऊंट, सियाचिन ग्लेशियर में काम करने वाले खच्चर, शिकारी पक्षी और सैन्य श्वान दस्ते सलामी मंच के सामने से गुजरे।

सेना के विभिन्न अंगों के करतबों के साथ इस वर्ष पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व 26 वर्षीय सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने किया। गुजरात में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली सिमरन ने गांधीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके साथ ही, यूरोपियन यूनियन की टुकड़ी ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। इस वर्ष की परेड में पहली बार भारतीय सेना ने रणभूमि व्यूह रचना यानी 'बैटल एरे' फॉर्मेट की झलक दिखाई, जिसमें परंपरागत मार्चिंग दस्ते और सेवा प्रस्तुतियां शामिल थीं।

अहमदाबाद मंडल पर 77वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया,डीआरएम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया,उत्कृष्ट रेलकर्मियों एवं बच्चों को किया सम्मानित

पहली तस्वीर में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। दूसरी तस्वीर में गणतंत्र दिवस संदेश वाचन करते हुए तथा अंतिम तस्वीर में रेलवे क्रिकेट ग्राउंड,साबरमती में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सामारोहिक परेड का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने अहमदाबाद स्थित रेलवे क्रिकेट ग्राउंड, साबरमती में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं रेल सुरक्षा बल,भारत स्काउट व गाइड व सिविल डिफ़ेंस यूनिटों की सयुंक्त परेड का निरीक्षण किया और मार्च-पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक,अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने सभी रेल कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा गणतंत्र दिवस के संदेश का वाचन किया।

इस दौरान मण्डल रेल प्रबंधक ने पश्चिम रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि रेल एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में इस वित्तीय वर्ष में 85 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज तथा 14 फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) चालू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक कवच (KAVACH) स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हाल ही में पश्चिम रेलवे का पहला कवच सिस्टम वडोदरा–अहमदाबाद खंड के 96 रूट किलोमीटर में 17 स्टेशनों को कवर करते हुए सफलतापूर्वक चालू किया गया है, जिसमें 13.7 किलोमीटर अहमदाबाद मंडल का भी शामिल है तथा अब तक 364 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम स्थापित किया है। चालू वित्त वर्ष में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। हिम्मतनगर–खेड़ब्रह्मा, विजापुर–आंबलियासण तथा आदरज मोटी–विजापुर रेल खंडों पर गेज परिवर्तन का कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, अहमदाबाद मंडल की सदस्याओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता 39 बच्चों को पुरस्कृत किया गया तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित दो रेल कर्मचारियों के परिजनों को 20,000–20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

फोटो कैप्शनःअपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन,अहमदाबाद की सदस्याएं गंभीर बीमारी से ग्रसित रेलकर्मी के परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए।

इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों एवं नृत्यों ने सभी को राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत कर दिया। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 62 रेल कर्मचारियों को प्रमाण पत्र एवं मैडल प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा चार विभागों के ग्रुप को सामुहिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के 15 विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।

इस समारोह में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन अहमदाबाद मंडल की टीम, सभी विभागों के शाखा अधिकारी, रेल अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

वरनामा और मकरपुरा के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा

सूरत-वडोदरा सेक्शन में वरनामा -मकरपुरा के बीच ब्रिज नंबर 570 के मौजूदा स्टील गर्डर्स को PSC स्लैब से बदलना हेतु अप लाइन पर 28 जनवरी एवं डाउन लाइन पर 29 जनवरी को ब्लाक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 28 और 29 जनवरी , 2026 को प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

28 जनवरी को रेगुलेट होने वाली ट्रेनेंः-

1. ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 28 जनवरी , 2026 को 1 घंटे 10 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 19012 दाहोद – वलसाड एक्सप्रेस 28 जनवरी , 2026 को 1 घंटे 10 मिनट रेगुलेट होगी।
3. ट्रेन संख्या 59050 वडोदरा - वलसाड पैसेंजर 28 जनवरी , 2026 को 40 मिनट रेगुलेट होगी।

29 जनवरी को रेगुलेट होने वाली ट्रेनेंः-

1. ट्रेन संख्या 12656 पुरैची थलाइवर - अहमदाबाद सुपरफास्ट 29 जनवरी ,2026 को 1 घंटे 10 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 09724 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर स्पेशल 29 जनवरी, 2026 को 1 घंटे रेगुलेट होगी।
3. ट्रेन संख्या 12471 बांद्रा टर्मिनस - श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट 29 जनवरी , 2026 को 30 मिनट रेगुलेट होगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

77वें गणतंत्र पर्व का राज्य स्तरीय समारोह : नवगठित वाव-थराद जिले के लिए गौरवशाली क्षण

▸▸ राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने फहराया तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विस अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की प्रेरक उपस्थिति : ध्वज वंदन समारोह की भव्यता एवं गरिमा और बढ़ी

▸▸ मार्च पास्ट, श्वान एवं अश्व शो सहित जवानों के हैरतअंगेज करतब देख प्रेक्षक हुए रोमांचित

▸▸ थराद के मलुपुर परेड ग्राउंड में विशाल जनसमूह के बीच वायु सेना के विमानों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगे को दिया विशेष सम्मान

गांधीनगर : विकास, विश्वास और विरासत का प्रतीक वाव-थराद जिले में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। थराद के मलुपुर परेड ग्राउंड में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा और भव्यता को और बढ़ा दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा कर तिरंगे की आन, बान और शान को उजागर किया। परेड मार्च पास्ट के माध्यम से शौर्य और समर्पण को उजागर करते पुलिस जवानों की विभिन्न 22 टुकड़ियों में शामिल कुल 810 जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।

राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और सलामी

देशभक्ति के उत्साह और उमंग से सराबोर वातावरण के बीच गुजरात की विकासगाथा को अविरत आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी सहित समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, समाज के अग्रणियों, अतिथियों, युवा पीढ़ी, महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने देशभक्ति के जोश के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। हर्ष ध्वनि ने राष्ट्रीय पर्व को और सुंदर बनाकर माहौल को देशभक्तिपूर्ण बना दिया।

मार्च पास्ट

पुलिस बैंड की समधुर धुनों के साथ पुलिस के जवानों की अनुशासनबद्ध परेड और मार्च-पास्ट आयोजित हुई। चेतक कमांडो, मरीन कमांडो, एसआरपी जवानों, पुलिस की विभिन्न महिला और पुरुष टुकड़ियों, एसपीसी, सैनिक स्कूल, एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों की इस परेड का उपस्थित सभी लोगों ने आनंद उठाया।

इसके अलावा, चेतक कमांडो के बुलेटप्रूफ वाहनों के निदर्शन (टेब्लो), हैरतअंगेज मोटरसाइकिल स्टंट शो तथा राज्य के गौरव गुजरात श्वान दल, गुजरात अश्व दल के सुंदर करतबों ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग द्वारा राज्यों के विभिन्न परंपरागत नृत्यों की प्रस्तुति के साथ वीर रस से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। स्कूली छात्रों ने अलग-अलग थीमों पर आधारित प्रस्तुतियां दीं।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मण्डल रेल प्रबंधक ने किया औचक निरीक्षण, स्वछता पर विशेष ज़ोर

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न "स्वच्छता ही सेवा" देश को स्वच्छ, स्वस्थ एवं जागरूक बनाने के संकल्प को साकार करते हुए मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने 26 जनवरी 2026 को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड, साबरमती में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने 4-5 घंटे तक स्टेशन परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का गहनता निरीक्षण किया तथा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, शौचालय, फुटओवर ब्रिज तथा अन्य स्थलों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी क्लीनिंग स्टाफ एवं सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे सफाई करने का तरीका,कौनसी मशीन का किस तरह एवं किस जगह उपयोग करना है आदि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कचरा निस्तारण, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, नियमित मॉनिटरिंग तथा स्वच्छता मानकों के पालन पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए।

इसके उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने पार्सल कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां कार्यरत स्टाफ से पार्सल हैंडलिंग, बुकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग तथा रिकॉर्ड संधारण की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा समयबद्ध और सुव्यवस्थित कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सुधारात्मक सुझाव एवं निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होने मेकेनिकल एवं कमर्शियल विभाग के अधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया एवं यातायात व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने यात्रियों एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए यातायात के सुचारु प्रवाह, पार्किंग प्रबंधन तथा ऑटो-टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कोसंबा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के सूरत–वडोदरा सेक्शन में स्थित कोसंबा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 28 जनवरी 2026 (बुधवार) को कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार हैः

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1. ट्रेन नं 59049 वलसाड - वडोदरा पैसेंजर ट्रेन 28 जनवरी को रद्द रहेगी
2. ट्रेन नं 59050 वडोदरा - वलसाड पैसेंजर ट्रेन 28 जनवरी को रद्द रहेगी
3. ट्रेन नं 69150 भरूच – सूरत मेमू ट्रेन 28 जनवरी को रद्द रहेगी

आंशिक रूप से रद्द

1. 28 जनवरी 2026 को ट्रेन नं 19101 विरार – भरूच एक्सप्रेस ट्रेन सूरत तक चलेगी तथा सूरत – भरूच के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दी 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्य की नगर पालिकाओं को बड़ी भेंट

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य की नगर पालिकाओं को 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के लिए नि:शुल्क सरकारी भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय

▸▸ विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे अब मुक्ति मिलेगी

▸▸ राज्य की 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से नागरिक सेवान्मुखी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नगरों शहरों में सार्वजनिक जनहितकारी परियोजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को निःशुल्क भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन अधिक पारदर्शी बने और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलें, इसके लिए नगर पालिकाओं को विकास कार्यों हेतु अब 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरलता से निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की लगभग 152 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी अधिक सरल बनेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा नगर पालिकाओं को सार्वजनिक सुविधा एवं जनकल्याण के परियोजनाओं के लिए निःशुल्क सरकारी भूमि देने के निर्णय के अनुसार; नगर सेवा सदन, फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत सीवर, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजना, सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज कार्य, आंगनवाड़ी, टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल, कन्वेंशन सेंटर जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हों; ऐसा सिटीजन-सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से विकास परियोजनाएं तेजी से शुरू हो सकेंगी और नगरों के विकास को और अधिक गति मिलेगी। नागरिकों को भी पानी, सीवर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी प्राथमिक सुविधाएं शीघ्रता से उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य की नगर पालिकाओं को 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के लिए निःशुल्क सरकारी भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय

▸▸ विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे अब मुक्ति मिलेगी

▸▸ राज्य की 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से नागरिक सेवान्मुखी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नगरों शहरों में सार्वजनिक जनहितकारी परियोजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को निःशुल्क भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

शहरी क्षेत्रों में प्रशासन अधिक पारदर्शी बने और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलें, इसके लिए नगर पालिकाओं को विकास कार्यों हेतु अब 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरलता से निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की लगभग 152 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी अधिक सरल बनेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा नगर पालिकाओं को सार्वजनिक सुविधा एवं जनकल्याण के परियोजनाओं के लिए निःशुल्क सरकारी भूमि देने के निर्णय के अनुसार; नगर सेवा सदन, फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत सीवर, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजना, सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज कार्य, आंगनवाड़ी, टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल, कन्वेंशन सेंटर जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हों; ऐसा सिटीजन-सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से विकास परियोजनाएं तेजी से शुरू हो सकेंगी और नगरों के विकास को और अधिक गति मिलेगी।

नागरिकों को भी पानी, सीवर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी प्राथमिक सुविधाएं शीघ्रता से उपलब्ध होंगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से 03 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्पेशल को 23 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09621 अजमेर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 22 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस – भगत की कोठी (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस – भगत की कोठी स्पेशल को 01 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड – हिसार (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 04728 वलसाड – हिसार स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04727 हिसार – वलसाड स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09622, 04828 एवं 04728 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 28 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।